

Disclaimer

The Institute has given the right of translation of the material in Hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

अस्वीकरण

भारतीय लेखाकार संस्थान ने इस अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार किसी को दिया था और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, इस अध्ययन विषय-वस्तु के मूल रूप की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है, फिर भी, यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

पेपर-4 - कॉर्पोरेट और आर्थिक कानून

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।

शेष पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें

प्रश्न 1

- (a) फार्मा लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है। कंपनी के 500 छोटे शेयरधारक हैं। 50 शेयरधारकों ने अमर को कंपनी के निदेशक मंडल में उनके प्रतिनिधि के रूप में निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। अमर के पास कथित कंपनी में ₹10 प्रत्येक के 1000 हिस्सेदारी शेयर हैं। बताएं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आलोक में, क्या अमर को छोटे शेयरधारकों के निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव कंपनी द्वारा अपनाया जा सकता है। यह भी बताएं कि कंपनी छोटे शेयरधारकों के निदेशक की नियुक्ति कर सकती है, अगर छोटे शेयरधारकों द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

(4 अंक)

- (b) पीसीआर लिमिटेड ने भारत में रहने वाले एक व्यक्ति श्री विवेक को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है जिन्होंने 1 जून, 2021 को पद का कार्यभार संभाला है। उन्हें स्वीकृत पारिश्रमिक पैकेज निम्नानुसार है:

क्रमांक संख्या	विवरण	₹
1	वेतन	60,00,000
2	किराए पर मुफ्त आवास	6,00,000
3	बाल शिक्षा भत्ता	3,00,000
4	यात्रा रियायत पैकेज छोड़ें	3,00,000
5	क्षतिपूर्ति के लिए लिए गए बीमा के संबंध में प्रीमियम	5,00,000

आगे यह भी बताया गया है कि-

- (a) श्री विवेक ने अवकाश यात्रा रियायत पैकेज का लाभ उठाया है जो 2021-22 के लिए यथानुपात नहीं होगा।
- (b) उपरोक्त बीमा पॉलिसी के संबंध में श्री विवेक वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दोषी सिद्ध नहीं होते हैं।

(c) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक के भुगतान के लिए एक विशेष संकल्प पारित नहीं किया है।

(d) कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान घाटा हुआ है।

(e) 31 मार्च, 2021 को कंपनी की प्रभावी पूंजी नकारात्मक है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए, आपसे निम्नलिखित का विश्लेषण करने और उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है:

(i) उस राशि की गणना करें जो विवेक को स्थापित करने के लिए मि. के वार्षिक पारिश्रमिक का गठन करेगी।

(ii) श्री विवेक को भुगतान किए गए अतिरिक्त पारिश्रमिक की गणना करें, यदि कोई हो, और उसकी वसूली की संभावनाओं पर चर्चा करें। (6 अंक)

(c) ग्रीन डेवलपर्स लिमिटेड ने उस भूमि पर एक वाणिज्यिक और आवासीय परिसर विकसित करने की परियोजना को निष्पादित करने के लिए ₹10.00 करोड़ के उचित बाजार मूल्य पर अपने निदेशक श्री मनोज के स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। विचार में, कंपनी परियोजना के पूरा होने पर श्री मनोज को समान मूल्य के कुछ प्लॉट आवंटित करेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल को सलाह दें कि क्या ग्रीन डेवलपर्स लिमिटेड प्रस्तावित व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है और यदि अनुपालन आवश्यकता का उल्लंघन होता है तो क्या होगा? (4 अंक)

उत्तर

(a) छोटे शेयरधारकों के निदेशक की नियुक्ति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 151 के अनुसार कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित

एक सूचीबद्ध कंपनी, नोटिस मिलने पर कम से कम:

(a) एक हजार छोटे शेयरधारक; नहीं तो

(b) ऐसे शेयरधारकों की कुल संख्या का 1/10वां भाग,

जो भी कम हो, छोटे शेयरधारकों द्वारा चुने गए छोटे शेयरधारकों के निदेशक हों।

हालांकि, एक सूचीबद्ध कंपनी छोटे शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वप्रेरणा से

एक निदेशक रखने का विकल्प चुन सकती है।

शब्द "छोटे शेयरधारक" का अर्थ है एक शेयरधारक 20,000 से अधिक के नाममात्र मूल्य के शेयर या ऐसी अन्य राशि जो निर्धारित की जा सकती है।

(i) श्री अमर को छोटे शेयरधारकों के निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव:

वर्तमान मामले में, चूंकि 50 छोटे शेयरधारकों ने अमर को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है, उक्त प्रस्ताव वैध है और इसे 500 छोटे शेयरधारकों के 1/10 के रूप में अपनाया जा सकता है। साथ ही, अमर के शेयरों का नाममात्र मूल्य ₹10,000 है (अर्थात् ₹10/- के 1000 हिस्सेदारी शेयर) जो ₹20,000 की अधिकतम सीमा से कम है।

(ii) यदि छोटे शेयरधारकों द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता है:

प्रश्न के दूसरे भाग के लिए, हां, कंपनी स्वतः संज्ञान लेकर छोटे शेयरधारकों के निदेशक की नियुक्ति कर सकती है, भले ही छोटे शेयरधारकों द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया हो।

(b) (i) राशि की गणना जो श्री विवेक के लिए वार्षिक पारिश्रमिक का गठन करेगी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2(78) के अनुसार, "पारिश्रमिक" शब्द का अर्थ किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए दिया गया या दिया गया कोई पैसा या इसके बराबर है और इसमें आयकर अधिनियम के तहत परिभाषित अनुलाभ शामिल हैं।, 1961।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 197(13) के अनुसार, जहां किसी कंपनी द्वारा प्रबंध निदेशक या अन्य प्रबंधकीय कर्मियों की ओर से कोई क्षतिपूर्ति बीमा लिया जाता है, तो कंपनी द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम ऐसे किसी भी पारिश्रमिक का हिस्सा नहीं होगा। कर्मियों, अगर वह व्यक्ति बीमा राशि के वर्ष के दौरान दोषी नहीं साबित होता है।

समस्या में प्रदान की गई जानकारी के आलोक में और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 197 के अनुसार, उस राशि की गणना जो पीसीआर लिमिटेड में श्री विवेक के वार्षिक पारिश्रमिक का गठन करेगी। वित्त वर्ष 2021-2022 इस प्रकार रहेगा:

क्रं सं	विवरण	में (10 महीने के अनुपात में क्योंकि
---------	-------	-------------------------------------

		एमडी ने 01.06.2021 से पद का कार्यभार संभाला है)
1.	वेतन	50,00,000
2.	किराए पर मुफ्त आवास	5,00,000
3.	बाल शिक्षा भत्ता	2,50,000
4	छुट्टी यात्रा रियायत पैकेज (प्रश्न के अनुसार 2021-22 के लिए यथानुपात नहीं)	3,00,000
	श्री विवेक का कुल वार्षिक पारिश्रमिक	60,50,000

नोट:

क्षतिपूर्ति के लिए लिए गए बीमा के संबंध में प्रीमियम पर विचार नहीं किया जाता है, जैसा कि वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान श्री विवेक दोषी साबित नहीं हुए।

(ii) श्री विवेक को दिए गए अतिरिक्त पारिश्रमिक की गणना

यह प्रदान किया जाता है कि कंपनी को वित्त वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के दौरान घाटा हुआ है और 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की प्रभावी पूंजी नकारात्मक है। इसलिए, अनुसूची V के साथ पठित अधिनियम के अनुसार, श्री विवेक को देय अधिकतम वार्षिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक अनुलाभ सहित ₹60 लाख होगा।

गणना की उपरोक्त तालिका से, श्री विवेक का कुल वार्षिक पारिश्रमिक ₹60,50,000 (अनुपातिक) आ गया है और जबकि, वर्ष 2021-2022 के लिए, श्री विवेक अधिकतम ₹50 के पारिश्रमिक के हकदार होंगे। लाख प्रति वर्ष (10 महीने के लिए यथानुपात)। इस प्रकार श्री विवेक को भुगतान किया गया अतिरिक्त पारिश्रमिक है ₹10,50,000/- [यानी ₹60,50,000 (-) ₹50,00,000]।

इसके ठीक होने की संभावनाएँ:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(9) और 197(10) के अनुसार, जहां किसी निदेशक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक सीमा से अधिक है, उसे ऐसे निदेशक द्वारा कंपनी को वापस कर दिया जाएगा और उस समय तक वह इसे कंपनी के लिए विश्वास पर अपने पास रखेगा।

कंपनी किसी भी राशि की वसूली से तब तक छूट नहीं देगी जो उसे वापस की जा सकती है जब तक कि राशि वापसी योग्य होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव द्वारा छूट को मंजूरी नहीं दी जाती है।

दिए गए मामले में, ₹10,50,000/- का स्वीकृत पारिश्रमिक पैकेज निर्धारित सीमा से अधिक है और जैसा कि प्रश्न में प्रदान किया गया है, अधिनियम की अनुसूची 5 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक के भुगतान के लिए कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया है।

इसलिए, कंपनी अतिरिक्त राशि की वसूली कर सकती है।

(c) नकदी के अलावा प्रतिफल के लिए संपत्ति अर्जित करने पर प्रतिबंध:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192(1) के अनुसार, कोई भी कंपनी ऐसी व्यवस्था नहीं करेगी जिसके द्वारा-

- (a) कंपनी का निदेशक या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति कंपनी से नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए संपत्ति अर्जित करता है या अर्जित करता है; या
- (b) कंपनी ऐसे निदेशक या इस तरह जुड़े व्यक्ति से नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए संपत्ति अर्जित करती है या अर्जित करती है।

प्रतिबंध में ढील:

उपरोक्त प्रतिबंध में ढील दी जाएगी अर्थात् कंपनी गैर-नकद लेनदेन से संबंधित एक व्यवस्था में प्रवेश कर सकती है जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि ऐसी व्यवस्था के लिए पूर्व अनुमोदन कंपनी के सामान्य बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा दिया जाता है।

समिति को सलाह दें:

इसलिए, कानून के उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर, ग्रीन डेवलपर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल को सलाह दी जाएगी कि कंपनी द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। हालांकि, प्रस्तावित व्यवस्था को क्रियान्वित किया जा सकता है, यदि एक सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी की पूर्व स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें विफल होने पर अनुबंध कंपनी के विकल्प पर शून्य हो जाएगा।

जहाँ निदेशक या जुड़ा व्यक्ति इसकी होल्डिंग कंपनी का निदेशक है, वहाँ होल्डिंग कंपनी की आम बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके अनुमोदन प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

यदि धारा 192 का उल्लंघन किया जाता है तो क्या होगा:

धारा 192 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था कंपनी के कहने पर शून्य हो जाएगी।

व्यवस्था शून्यकरणीय नहीं होगी;

- (a) यदि किसी धन या अन्य प्रतिफल की बहाली जो व्यवस्था की विषय-वस्तु है, अब संभव नहीं है और कंपनी को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की गई है; या
- (b) यदि कोई अधिकार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस धारा (अर्थात् धारा 192) के प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना के बिना मूल्य के लिए वास्तविक रूप से अर्जित किया जाता है।

इसलिए, ग्रीन डेवलपर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित व्यवस्था में प्रवेश कर सकते हैं।

प्रश्न 2

(a) एसटीसी लिमिटेड एचटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसटीसी लिमिटेड के 100% हिस्सेदारी शेयर, पूरी तरह से भुगतान किए गए, एचटीसी लिमिटेड के पास हैं, जिसमें एचटीसी लिमिटेड के 6 नामांकित शेयर शामिल हैं। संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, दोनों कंपनियों के विलय के लिए एचटीसी लिमिटेड की समिति बैठक में एक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। एचटीसी लिमिटेड के अधिकांश निदेशकों ने समिति की बैठक में कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 के प्रावधानों के अनुसार विलय को फास्ट ट्रैक प्रणाली के माध्यम से किया जाना है। हालाँकि, कंपनी सचिव का विचार था कि दोनों कंपनियों का विलय फास्ट ट्रैक प्रणाली के माध्यम से नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सार्वजनिक कंपनियाँ हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए-

- (i) फास्ट ट्रैक प्रणाली के माध्यम से एचटीसी लिमिटेड और एसटीसी लिमिटेड के विलय की वैधता का विश्लेषण करें।
- (ii) जांच करें कि क्या एचटीसी लिमिटेड एक विदेशी कंपनी है, तो क्या एसटीसी लिमिटेड का एचटीसी लिमिटेड में विलय किया जा सकता है।

(4 अंक)

(b) एसओपी लिमिटेड खिलाड़ियों के निर्माण के क्षेत्र में है। कंपनी के पास ₹50 लाख की अधिकृत

शेयर पूंजी है, जिसमें प्रत्येक ₹100 के 40,000 हिस्सेदारी शेयर और ₹100 के 10,000 वरीयता शेयर शामिल हैं। कंपनी ने 32,000 हिस्सेदारी शेयर और 8,000 अधिमान शेयर जारी किए हैं, जिनमें से 24,000 हिस्सेदारी शेयर और 6,000 अधिमान शेयर अभिदत्त किए गए हैं और पूरी तरह से पेड-अप हैं। कंपनी के पास हिस्सेदारी शेयर रखने वाले 650 सदस्य हैं और वरीयता शेयर रखने वाले 200 सदस्य हैं। कंपनी के 3,100 हिस्सेदारी शेयर रखने वाले 90 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कंपनी की ओर से उत्पीड़न और कुप्रबंधन के विभिन्न कृत्यों का आरोप लगाया गया था। याचिका के लंबित रहने के दौरान, 10 याचिकाकर्ता-सदस्य जिनके पास 1,000 हिस्सेदारी शेयर थे, याचिका से अलग हो गए। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित का उत्तर दें:

(i) क्या याचिका स्वीकार की जाएगी?

(ii) क्या कथित सदस्यों के अलग होने के बाद याचिका सुनवाई योग्य होगी?

(4 अंक)

(c) 1 अप्रैल, 2020 को, खाद्य संसाधक निर्माण इकाई में लगी कंपनी, एल्म फूडप्रोसेसर लिमिटेड ने खाद्य संसाधक के सबसे बड़े निर्माता, रॉन एंड कोल लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया। दोनों कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत हैं। संयुक्त उद्यम समझौते में मध्यस्थता के लिए आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित विवाद को संदर्भित करने की अवधि शामिल नहीं है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के आलोक में, जांच करें कि क्या होगा, यदि पार्टियां बाद में 2021 में आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए सहमत हो गईं?

(3 अंक)

(d) एलएमआर लिमिटेड, एक बैंकिंग कंपनी की एक "लेखन संरक्षण नीति" है, जो अन्य बातों के साथ-साथ खाता बंद होने के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने ग्राहकों और लाभार्थी मालिकों की पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए कहती है। मूल्यांकन करें, क्या कंपनी की "लेखन संरक्षण नीति" ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अपने ऋण को पूरा किया है?

(3 अंक)

उत्तर

(a) (i) कंपनियां जो विलय या समामेलन की योजना में प्रवेश कर सकती हैं [उप-धारा (1)]:

विलय या समामेलन की योजना दो या दो से अधिक छोटी कंपनियों के बीच या एक धारण कंपनी और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी या कंपनियों के वर्ग या

वर्गों के बीच निर्धारित की जा सकती है (यानी दो या अधिक स्टार्ट-अप कंपनियों या एक या एक या एक से अधिक छोटी कंपनी के साथ अधिक स्टार्ट अप कंपनी) अगर इसकी 100% शेयर पूंजी धारण कंपनी के पास है, नामांकित या नामांकित लोगों के शेयरों को छोड़कर यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायक कंपनी के सदस्यों की संख्या वैधानिक से कम नहीं है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 187 में प्रदान की गई सीमा।

फास्ट ट्रैक प्रणाली के माध्यम से एचटीसी लिमिटेड और एसटीसी लिमिटेड के विलय की वैधता।

वर्तमान मामले में, एसटीसी लिमिटेड के 100% हिस्सेदारी शेयर एचटीसी लिमिटेड के पास हैं, जिसमें एचटीसी लिमिटेड के 6 नामांकित शेयर शामिल हैं।

हां, एचटीसी लिमिटेड और एसटीसी लिमिटेड के विलय का प्रस्ताव फास्ट ट्रैक प्रणाली के माध्यम से निदेशक मंडल द्वारा दिया गया, निम्नलिखित के अधीन मान्य होगा:

-

- (a) आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने वाली प्रस्तावित योजना की सूचना, यदि रजिस्ट्रार और आधिकारिक परिसमापक से जहाँ संबंधित कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय स्थित हैं या योजना से प्रभावित व्यक्तियों को तीस दिनों के भीतर हस्तांतरणकर्ता कंपनी या कंपनियों और हस्तांतरी कंपनी द्वारा जारी किया जाता है;
- (b) प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर कंपनियों द्वारा विचार किया जाता है उनकी संबंधित आम बैठकों में और योजना को संबंधित सदस्यों या सदस्यों के वर्ग द्वारा एक सामान्य बैठक में कम से कम शेयरों की कुल संख्या में से नब्बे प्रतिशत की मंजूरी दी जाती है।
- (c) विलय में शामिल प्रत्येक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान के रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रपत्र में शोधन क्षमता की घोषणा दाखिल करती है; तथा
- (d) इस योजना को इस उद्देश्य के लिए अपने लेनदारों को योजना के साथ इक्कीस दिनों का नोटिस देकर या लिखित रूप में कंपनी द्वारा बुलाई गई बैठक में इंगित संबंधित कंपनियों के लेनदारों या लेनदारों के वर्ग के मूल्य में नौ-दसवें का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कंपनी सचिव का तर्क कि दोनों कंपनियों का विलय फास्ट ट्रैक प्रणाली के माध्यम से नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सार्वजनिक कंपनियां हैं, गलत है।

(ii) एक विदेशी कंपनी एचटीसी लिमिटेड के साथ एसटीसी लिमिटेड का विलय:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 234 सीमा पार विलय और समामेलन के संबंध में यानी भारतीय कंपनी और एक विदेशी निकाय निगमित के बीच प्रावधान करती है। कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 25A में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस खंड के अनुसार, एसटीसी लिमिटेड को एचटीसी लिमिटेड (यदि यह एक विदेशी कंपनी है) के साथ आरबीआई की मंजूरी के साथ और अधिनियम की धारा 230 से 232 के प्रावधानों और संबंधित नियमों के अनुपालन के बाद विलय किया जा सकता है।

(b) उत्पीड़न और कुप्रबंधन के लिए आवेदन करने का अधिकार:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 244 के प्रावधानों के अनुसार, शेयर पूँजीवाली कंपनी के मामले में, उत्पीड़न और कुप्रबंधन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र सदस्य निम्न में से सबसे कम होंगे:

- ♦ 100 सदस्य; या
- ♦ सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां; या
- ♦ कंपनी की जारी शेयर पूँजीके कम से कम 1/10 भाग रखने वाले सदस्य।

बशर्ते कि आवेदक या आवेदकों ने अपने या अपने शेयरों पर देय सभी कॉलस और अन्य राशियों का भुगतान कर दिया हो या कर दिया हो।

एसओपीएस लिमिटेड का शेयर धारण प्रतिरूप इस प्रकार दिया गया है:

₹40,00,000 जारी शेयर पूँजी (हिस्सेदारी और वरीयता) 850 सदस्यों द्वारा धारित

कुछ सदस्यों द्वारा उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए याचिका इस प्रकार दी गई है:

(i) याचिका करने वाले सदस्यों की संख्या - 90 सदस्य जिनके पास ₹100/- के 3100 हिस्सेदारी शेयर हैं।

(ii) याचिका दायर करने वाले सदस्यों द्वारा धारित शेयर पूँजीकी राशि - ₹3,10,000

याचिका वैध होगी यदि यह निम्न में से निम्नतम द्वारा की गई है:

- 100 सदस्य; या
- 85 सदस्य (850 का 1/ 30th ाँ); या

- ₹4,00,000 शेयर पूँजीरखने वाले सदस्य (₹40,00,000 का 1/10वां हिस्सा होने के नाते)

(i) क्या याचिका पोषणीय है ?

जैसा कि स्पष्ट है, 90 सदस्यों द्वारा की गई याचिका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 244 के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करती है क्योंकि यह इस मामले में 85 सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है। इसलिए याचिका विचारणीय है।

(ii) क्या कथित सदस्यों के अलग होने के बाद भी याचिका पोषणीय है? एक शेयरधारक द्वारा दी जाने वाली सहमति को कार्यवाही की शुरुआत में माना जाता है। कार्यवाही के दौरान किसी भी शेयरधारक द्वारा सहमति वापस लेने से याचिका की स्थिरता प्रभावित नहीं होगी [राजामुंदरी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन बनाम वी. नागेश्वर राव ए.आई.आर.]।

इसलिए, 1,000 हिस्सेदारी शेयर रखने वाले 10 याचिकाकर्ता सदस्यों द्वारा बताए गए सदस्यों यानी 10 याचिकाकर्ता सदस्यों के अलग होने के बाद भी याचिका कायम रहेगी।

- (c) दिए गए प्रश्न में, एएलएम फूड प्रोसेसर लिमिटेड और रॉन एंड कोल लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम समझौते (जेवीए) में मध्यस्थता के लिए आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित विवाद को संदर्भित करने के लिए शब्द नहीं है। इस विवाद को हल करने के लिए, पार्टियों ने बाद में 2021 में आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए एक समझौता किया। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार, मध्यस्थता समझौते का उद्देश्य विवादों को मध्यस्थता के लिए इस आधार पर प्रस्तुत करना है कि क्या मौजूदा या भविष्य के विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। जहां विवाद उत्पन्न होने के बाद एक समझौता किया जाता है, तो इसे 'प्रस्तुतीकरण समझौता' कहा जाएगा।

निष्कर्ष: इस प्रकार, पार्टियों द्वारा एक प्रस्तुतीकरण समझौता दर्ज किया जा सकता है जिसे मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे वे मध्यस्थ के निर्णय का पालन करने के लिए सहमत होंगे।

- (d) धन परिशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 12 बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों यानी सूचना इकाई के सभी लेनदेन के लेखन बनाए रखने के ऋण के लिए

प्रदान करती है।

उप-धारा (1)(ई) के अनुसार, प्रत्येक सूचना इकाई अपने ग्राहकों और लाभार्थी स्वामियों की पहचान के साक्ष्य के साथ-साथ अपने ग्राहकों से संबंधित खाता फाइलों और व्यापार पत्राचार का लेखन बनाए रखेगी।

रिकॉर्ड का रखरखाव: अपने ग्राहकों और लाभकारी मालिकों की पहचान के साथ-साथ खाते की फाइलों और अपने ग्राहकों से संबंधित व्यापार पत्राचार के दस्तावेजों के उप-धारा (1) के खंड (e) में संदर्भित अभिलेख एक ग्राहक और सूचना देने वाली इकाई के बीच व्यावसायिक संबंध समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद, जो भी बाद में हो, पांच साल की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।

धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के संबंधित नियमों के अनुसार लेखन में लेनदेन की प्रकृति, लेनदेन की राशि, मुद्रा, लेनदेन की तारीख और लेनदेन के पक्ष के बारे में जानकारी शामिल होगी।

निष्कर्ष

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एलएमआर लिमिटेड ने ग्राहक और कंपनी के बीच व्यापार संबंध समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद, जो भी बाद में हो, 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊपर बताए गए दस्तावेजों को बनाए रखने के अपने ऋण को पूरा नहीं किया है। कंपनी की संरक्षण नीति ऊपर बताई गई ऐसी शर्तें प्रदान नहीं करती है।

प्रश्न 3

(a) ग्रीन रोज़ लिमिटेड नियमित रूप से कंपनी पंजीयक (आरओसी) के साथ अपने वार्षिक वित्तीय विवरण दाखिल कर रहा है। कंपनी पिछले 5 वर्ष से लगातार घाटे में चल रही है। वार्षिक वित्तीय विवरणों ने खुलासा किया कि नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार देनदारियां इसकी संपत्ति का दस गुना हैं। अपने कार्यालय के साथ दायर वित्तीय विवरणों से पता चला वित्तीय स्थिति के आधार पर, आरओसी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कंपनी को अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण जनहित में घायल होना चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 272 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 272 के तहत आरओसी ने न्यायाधिकरण [एनसीएलटी] के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसके लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कंपनी को बंद कर दिया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए।

(i) उन परिस्थितियों को गिनाइए जिनमें न्यायाधिकरण द्वारा एक कंपनी का परिसमापन

किया जा सकता है।

(ii) आरओसी द्वारा दायर याचिका की वैधता की जांच करें।

(4 अंक)

- (b) आरएफसी लिमिटेड को सिंगापुर में शामिल किया गया है और इसका मुंबई में एक व्यावसायिक स्थान है। कंपनी ने 100 अमेरिकी डॉलर के 5,00,000 शेयर जारी किए हैं, जिसमें 4,00,000 हिस्सेदारी शेयर और 1,00,000 अधिमान शेयर शामिल हैं। जारी की गई शेयर पूंजी पूरी तरह से 5,000 वरीयता वाले शेयरों को छोड़कर पूरी तरह से भुगतान की जाती है, जहां प्रति शेयर 50 अमेरिकी डॉलर का भुगतान नहीं किया जाता है।

आरजेडब्ल्यू, एक भारतीय नागरिक के पास 26,000 वरीयता शेयर हैं जिनमें 1100 आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर शामिल हैं और नई दिल्ली (भारत) में शामिल रॉटे लिमिटेड के पास आरएफसी लिमिटेड में 2,23,500 हिस्सेदारी शेयर हैं।

कंपनी पंजीयक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 379 के तहत उस व्यक्ति को संबोधित नोटिस जारी किया, जिसका नाम और पता विदेशी कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुपालन के लिए आरएफसी लिमिटेड द्वारा पंजीयक को दिया गया है।

उपरोक्त नोटिस उस पते पर दिया गया था जो आरएफसी लिमिटेड द्वारा कंपनी पंजीयक को दिया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए निम्नलिखित के उत्तर दें:

(i) क्या आरएफसी लिमिटेड एक विदेशी कंपनी है?

(ii) क्या कंपनियों के पंजीयक द्वारा नोटिस की तामील वैध है?

(4 अंक)

- (c) टीजेड दुनिया के विभिन्न देशों में सॉफ्टवेयर उत्पादों के निर्यात में लगेइंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के एक प्रवर्तक निदेशक हैं। जेडजेड, अमेरिका में एक ग्राहक जिसे कंपनी ने कुछ उत्पादों का निर्यात किया, इन निर्यातों के लिए देय राशि का भुगतान करने में विफल रही। बाद में, कंपनी ने जेड के साथ 50% राशि का निपटान किया और यह राशि हवाला के माध्यम से भारत में स्थानांतरित कर दी गई। प्राप्त धन का उपयोग कंपनी द्वारा आंशिक रूप से मुंबई में अपने कार्यालय भवन को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था और शेष राशि का उपयोग आंशिक रूप से दिल्ली में आवासीय फ्लैट को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था, जिसे टीसी द्वारा खरीदा गया था, जो टीजेड का बेटा है। हवाला व्यवसायी के परिसरों में तलाशी के दौरान, खोज अधिकारी द्वारा कुछ दस्तावेजी साक्ष्य

प्राप्त किए गए और जिसके आधार पर, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने आईएनडी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के कार्यालय और फ्लैट को कुर्क करने का आदेश जारी किया। टीसी पर धन परिशोधन के अनुसूचित अपराध में शामिल होने का आरोप है।

उपरोक्त परिदृश्य के आधार पर, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित का उत्तर दें:

- (i) अनुसूचित अपराध क्या है?
- (ii) जहां जब्ती का आदेश दिया गया है, ऐसी संपत्ति में सभी अधिकार और शीर्षक भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगे। कथन की जांच करें।
- (iii) अधिनियम के तहत उपलब्ध उपाय के बारे में आईएनडी एक्सपोर्ट लिमिटेड को सलाह दें। (6 अंक)

उत्तर

(a) (i) न्यायाधिकरण द्वारा समापन वाली परिस्थितियाँ:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 के अनुसार, एक कंपनी को न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त किया जा सकता है, जहां-

- (a) यदि कंपनी ने, विशेष प्रस्ताव द्वारा, कंपनी को न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त करने का प्रस्ताव लिया है;
- (b) कंपनी ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों के खिलाफ काम किया है।
- (c) पंजीयक या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर। अधिकरण की राय है कि कंपनी के मामलों को कपटपूर्ण तरीके से संचालित किया गया है या कंपनी का गठन धोखाधड़ी और गैरकानूनी उद्देश्य के लिए किया गया है या इसके मामलों के गठन या प्रबंधन से संबंधित व्यक्ति धोखाधड़ी, दुर्यवहार या कदाचार के दोषी हैं और यह उचित है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए।
- (d) यदि कंपनी ने पंजीयक के पास लगातार पांच वित्तीय वर्षों के लिए अपने वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में चूक की है; या
- (e) अधिकरण की राय है कि यह उचित और न्यायसंगत है कि कंपनी को बंद कर

दिया जाना चाहिए।

(ii) आरओसी द्वारा दायर याचिका की वैधता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 272 के अनुसार, कंपनी पंजीयक धारा 271 के खंड (ए) में निर्दिष्ट आधारों को छोड़कर, धारा 271 के तहत समापन के लिए एक याचिका पेश करने का हकदार है।

बशर्ते कि रजिस्ट्रार एक याचिका की प्रस्तुति के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा: केंद्र सरकार को अपनी मंजूरी तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि कंपनी को अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दिया गया हो।

यहां दिए गए उदाहरण में, आरओसी ने न्यायाधिकरण के समक्ष केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना समापन के लिए एक याचिका दायर की।

इसलिए, आरओसी द्वारा दायर याचिका अमान्य है।

(b) (i) क्या आरएफसी लिमिटेड एक विदेशी कंपनी है?

एक विदेशी कंपनी की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(42) के अनुसार, "विदेशी कंपनी" का अर्थ भारत के बाहर निगमित कोई भी कंपनी या निगमित निकाय है, जिसका भारत में व्यवसाय का स्थान है चाहे स्वयं या किसी दलाल के माध्यम से, भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से; और भारत में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का संचालन करता है।

धारा 379(2) का प्रावधान: विदेशी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी रखने की आवश्यकता:

इसके अलावा, समस्या में दिए गए इनपुट के आलोक में, जहां प्रदत्त शेयर पूंजी का 50% से कम नहीं है, चाहे हिस्सेदारी या वरीयता या आंशिक हिस्सेदारी और आंशिक वरीयता, भारत के बाहर निगमित एक विदेशी कंपनी के पास एक या भारत के अधिक नागरिक और भारत में निगमित एक या एक से अधिक कंपनियां या निकाय, चाहे अकेले या समग्र रूप से, ऐसी विदेशी कंपनी भी अध्याय XXII के प्रावधानों और इस अधिनियम के ऐसे अन्य प्रावधानों का पालन करेगी जैसा कि संबंधित के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है। भारत में इसके द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय मानो भारत में निगमित कंपनी हो। [धारा 379 (2)]

दिए गए मामले में, सिंगापुर में शामिल आरएफसी लिमिटेड का मुंबई में एक व्यावसायिक स्थान है। कंपनी ने यूएसडी 100 के 5,00,000 शेयर जारी किए हैं,

जिनमें से प्रत्येक यूएसडी 5,00,00,000 है, जिसमें USD 4,00,00,000 हिस्सेदारी शेयर पूंजी (यानी 4 लाख * यूएसडी 100) और यूएसडी 1,00,00,000 वरीयता शेयर पूंजी शामिल है (यानी, 1 लाख * यूएसडी 100)।

चूंकि जारी की गई पूंजी पूरी तरह से 5,000 वरीयता शेयरों (यानी, 5000 * 50 = यूएसडी 2,50,000) को छोड़कर पूरी तरह से भुगतान की गई थी, इसलिए, आरएफसी लिमिटेड की कुल भुगतान की गई शेयर पूंजी है:

इक्विटी शेयर पूंजी	USD 4,00,00,000
वरीयता शेयर पूंजी (पूर्ण भुगतान)	USD 95,00,000
वरीयता शेयर पूंजी (आंशिक रूप से भुगतान)	USD 2,50,000
कुल पेड-अप शेयर पूंजी	USD 4,97,50,000

तथ्यों के अनुसार, आरजेडब्ल्यू द्वारा शेयरधारण , एक भारतीय नागरिक यूएसडी 25,45,000 वरीयता शेयर कैपिटल (यानी 26,000 शेयर * यूएसडी 100- 1100 शेयर * यूएसडी 50) है और नई दिल्ली (भारत) में शामिल रॉटे लिमिटेड के पास यूएसडी 2,23 है आरएफसी लिमिटेड में 50,000 हिस्सेदारी शेयर पूंजी (अर्थात, 2,23,500 * यूएसडी 100)। सकल शेयरधारिता यूएसडी 2,48,95,000 है।

धारा 379(2) की आवश्यकता के अनुसार, आरजेडब्ल्यू, एक भारतीय नागरिक और रॉटे लिमिटेड निगमित (एक भारतीय कंपनी) के पास 50% से अधिक शेयरधारिता थी (अर्थात 50% * यूएसडी 4,97,50,000 = 2,48,75,000) आरएफसी लिमिटेड में।

इसलिए, आरएफसी लिमिटेड न केवल धारा 2(42) के अनुसार एक विदेशी कंपनी है, बल्कि भारत में इसके द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अध्याय XXII के प्रावधानों और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों का भी अनुपालन करेगी, जैसे कि यह धारा 397(2) के अनुसार भारत में निगमित एक कंपनी।

(ii) क्या आरओसी द्वारा नोटिस की सेवा वैध है?

हां, कंपनी पंजीयक द्वारा नोटिस की सेवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 383 के आलोक में मान्य है। प्रावधान के अनुसार किसी विदेशी कंपनी को तामील किए जाने के लिए आवश्यक कोई भी प्रक्रिया, नोटिस, या अन्य दस्तावेज पर्याप्त रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे, यदि किसी व्यक्ति को संबोधित किया गया है जिसका नाम और पता पंजीयक को दिया गया है और छोड़ा गया है, या भेजा गया है। डाक द्वारा, उस पते पर जो पंजीयक को या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा दिया गया है।

(c) (i) अनुसूचित अपराध

शब्द "अनुसूचित अपराध" को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (y) में परिभाषित किया गया है। का मतलब है -

- (a) अनुसूची के भाग A के तहत निर्दिष्ट अपराध; या
- (b) अनुसूची के भाग बी के तहत निर्दिष्ट अपराध यदि ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य एक करोड़ रुपये या उससे अधिक है; या
- (c) अनुसूची के भाग C के तहत निर्दिष्ट अपराध।

(ii) क्या संपत्ति में सभी अधिकार और शीर्षक भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं

धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 की धारा 9 के अनुसार, जहां किसी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति के संबंध में जब्ती का आदेश पारित किया गया है, ऐसी संपत्ति में सभी अधिकार और शीर्षक पूरी तरह से सभी बाधाओं से मुक्त केंद्र सरकार में निहित होंगे। . इसलिए, यह कथन कि संपत्ति में अधिकार और शीर्षक अधिहरण के आदेश के पारित होने पर भारत के राष्ट्रपति में निहित होगा, गलत है।

(iii) उपाय उपलब्ध

धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 की धारा 5 के अनुसार, आईएनडी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को अपने कार्यालय का आनंद लेने या उपयोग करने का अधिकार होगा। टीजेड के बेटे टीसी द्वारा खरीदा गया फ्लैट यहां एक इच्छुक व्यक्ति होने के नाते अनंतिम कुर्की की अवधि के दौरान अधिकारों का आनंद ले सकता है।

साथ ही, अधिनियम की धारा 26 और 42 के तहत, आईएनडी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, यदि कुर्की आदेश पर न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा किए गए एक आदेश से व्यथित है, तो वह अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किए गए आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर की जाएगी और अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में आगे अपील की जाएगी।

प्रश्न 4

(a) एबीसी लिमिटेड ने "कैश-डाउन पेमेंट स्कीम" के तहत भूखंडों के विकास के लिए जनता से धन जुटाया। उक्त योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित नियमों और शर्तों को निर्धारित करती है।

- (i) एग्रीमेंट की तारीख से 9 महीने पूरे होने के बाद ग्राहक को प्लॉट आवंटित किया जाएगा।

- (ii) समझौते में प्रवेश के समय किसी विशिष्ट भूखंड का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (iii) कंपनी के पास भूखंडों के विकास और रखरखाव का अधिकार है।
- (iv) योजना के तहत जुटाई गई राशि का उपयोग योजना के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
- (v) भूखंडों के विकास पर ग्राहकों का दिन-प्रतिदिन नियंत्रण नहीं होता है।

अन्य सूचना:

- (i) यह योजना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय समिति [सेबी] के साथ पंजीकृत है।
 - (ii) कंपनी ने योजना के तहत ₹100 करोड़ जुटाए थे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय समिति अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का हवाला देते हुए और उनका विश्लेषण करते हुए निर्णय लें:
- (i) क्या एबीसी लिमिटेड द्वारा संचालित "कैश-डाउन पेमेंट स्कीम" एक सामूहिक निवेश योजना है।
 - (ii) योजना सेबी के साथ पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में आपका क्या उत्तर होगा?

(4 अंक)

- (b) 'सेबी के पास संघर्ष विराम आदेश पारित करने की शक्तियां हैं'। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय समिति अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।
(4 अंक)
- (c) श्री एमजीजे, भारत के बाहर रहने वाले एक व्यक्ति, बेंगलूर (भारत) में वाणिज्यिक और आवासीय परिसर से युक्त एक विशाल बस्ती विकास परियोजना में लगी एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी योगदान के माध्यम से अपने विदेशी मुद्रा निधियों का निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का हवाला देते हुए उक्त कंपनी में निवेश करने के उनके प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जाँच करें। (3 अंक)
- (d) सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को कोचिंग और छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उपलायम ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का गठन किया गया था। भारतीय मूल के श्री मुरुगन ने अमेरिकी नागरिकता हासिल की और यूएसए में बस गए। हालाँकि, वह भारत का एक विदेशी नागरिक कार्डधारक है। श्री मुरुगन ने सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत बचत से उक्त एसोसिएशन को ₹10 लाख का दान दिया।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए निम्नलिखित के उत्तर दीजिए:

- (i) क्या श्री मुरुगन द्वारा दिया गया दान विदेशी योगदान है?
- (ii) यदि श्री मुरुगन अभी भी भारतीय नागरिकता रखते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा?

(3 अंक)

उत्तर

- (a) "सामूहिक निवेश योजना" का अर्थ किसी भी योजना या व्यवस्था से है जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम समिति अधिनियम, 1992 [धारा 2(1)(बीए)] की धारा 11ए में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है।

सामूहिक निवेश योजना [धारा 11AA]: कोई भी योजना या व्यवस्था जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, उप-धारा (2) या उप-धारा (2ए) में निर्दिष्ट एक सामूहिक निवेश योजना होगी।

बशर्ते कि किसी योजना या व्यवस्था के तहत निधियों का पूलिंग, जो समिति के साथ पंजीकृत नहीं है, जिसमें एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि शामिल है, को एक सामूहिक निवेश योजना माना जाएगा।

आवश्यक शर्तें [धारा 11AA(2)]: किसी व्यक्ति द्वारा की गई या प्रस्तावित कोई योजना या व्यवस्था जिसके तहत-

- (i) निवेशकों द्वारा किए गए योगदान, या भुगतान, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, योजना या व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए जमा और उपयोग किया जाता है;
- (ii) ऐसी योजना या व्यवस्था से लाभ, आय, उपज या संपत्ति, प्राप्त करने की दृष्टि से निवेशकों द्वारा ऐसी योजना या व्यवस्था में योगदान या भुगतान किया जाता है;
- (iii) संपत्ति, योगदान या निवेश जो योजना या व्यवस्था का हिस्सा है, चाहे पहचान योग्य हो या नहीं, निवेशकों की ओर से प्रबंधित किया जाता है;
- (iv) योजना या व्यवस्था के प्रबंधन और संचालन पर निवेशकों का दिन-प्रतिदिन का नियंत्रण नहीं होता है। [उप-धारा (2)]

धारा 11AA(2A): इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई या पेश की गई कोई भी योजना या व्यवस्था।

तदनुसार, उत्तर निम्नलिखित हैं:

- (i) हां, एबीसी लिमिटेड द्वारा संचालित "कैश-डाउन पेमेंट स्कीम" अपेक्षित शर्तों के अनुपालन में एक सामूहिक निवेश योजना है और सेबी के साथ पंजीकृत है।
- (ii) दिए गए मामले में, यदि योजना सेबी के साथ पंजीकृत नहीं है, तो किसी भी योजना के तहत धन की पूलिंग, जिसमें एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि शामिल है, को सामूहिक निवेश योजना माना जाएगा।

इसलिए उत्तर वही रहेगा।

- (b) सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11डी के अनुसार, अगर समिति को पता चलता है कि जांच करने के बाद कोई व्यक्ति-

- (i) उल्लंघन किया है, या
- (ii) उल्लंघन करने की संभावना है

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान, या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम।

यह ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसमें ऐसे व्यक्ति को ऐसा उल्लंघन करने या ऐसा करने से रोकने और रोकने के लिए कहा जा सकता है।

बशर्ते कि बोर्ड किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी (धारा 12 के तहत निर्दिष्ट मध्यस्थों के अलावा) के संबंध में ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा, जो किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का इरादा रखता है, जब तक कि बोर्ड के पास यह मानने का उचित आधार न हो कि ऐसी कंपनी ने व्यापार या बाजार में हेरफेर किया है।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह कथन कि सेबी के पास संघर्ष विराम आदेश पारित करने की शक्तियां हैं, सेबी अधिनियम की धारा 11(डी) में प्रदान की गई शर्तों के अधीन सही है। 1992.

- (c) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) विनियम, 2000 के अनुसार, भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को भारत में किसी भी कंपनी, या साझेदारी फर्म या मालिकाना प्रतिष्ठान या किसी संस्था में, चाहे वह शामिल हो या नहीं, भारत में निवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। अचल संपत्ति व्यवसाय, या फार्म हाउस के निर्माण में संलग्न है या संलग्न होने का प्रस्ताव है।

यहां "रियल एस्टेट व्यवसाय" शब्द में सेबी (आरईआईटी) विनियम 2014 के तहत पंजीकृत और विनियमित बस्ती का विकास, आवासीय / वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों या पुलों और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) का निर्माण शामिल नहीं होगा।

निष्कर्ष: तदनुसार, श्री एमजीजे द्वारा एक भारतीय कंपनी में धन निवेश करने का प्रस्ताव व्यवहार्य है क्योंकि निवेश उपर्युक्त कानूनों के अनुसार बस्ती के विकास के लिए है।

(d) विदेशी योगदान:

विदेशी योगदान को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए, 2010) की धारा 2(1)(एच) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है किसी विदेशी स्रोत द्वारा किया गया दान, वितरण या हस्तांतरण। धारा 2(1)(j) विदेशी स्रोत को समावेशी रूप से परिभाषित करते हुए केवल एक विदेशी देश के नागरिक के बारे में बताती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु, मुद्रा या विदेशी सुरक्षा का दान, वितरण या हस्तांतरण, जिसने इसे किसी विदेशी स्रोत से सीधे या एक या अधिक व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त किया है, एक विदेशी योगदान है।

(i) क्या श्री मुरुगन द्वारा किया गया दान विदेशी स्रोत है? हाँ। श्री मुरुगन, भारतीय मूल के एक व्यक्ति, जिन्होंने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली है और भारत के एक विदेशी नागरिक कार्डधारक भी हैं, से दान को विदेशी योगदान के रूप में माना जाएगा।

(ii) मामले में अगर श्री मुरुगन अभी भी भारतीय नागरिकता रखते हैं

किसी अन्य देश (अर्थात्, अनिवासी भारतीय) में रहने वाले भारत के नागरिक द्वारा, अपनी व्यक्तिगत बचत से, सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए योगदान को विदेशी योगदान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यदि श्री मुरुगन भारतीय नागरिकता रखते हैं, तो वे विदेशी नहीं हैं और इसलिए, श्री मुरुगन द्वारा दिया गया दान, विदेशी योगदान नहीं माना जाएगा।

प्रश्न 5

(a) ब्लो (निधि) लिमिटेड के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण से निम्नलिखित शेष राशि निकाली गई है।

विवरण (ब्यौरा)	राशि ₹ में
प्रदत्त हिस्सेदारी शेयर पूंजी	15,00,000
प्रदत्त वरीयता शेयर पूंजी	5,00,000
मुक्त संचय	1,00,000

मूर्त संपत्ति	10,00,000
अमूर्त संपत्ति	2,00,000

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत तैयार किए गए समय-समय पर संशोधित निधि नियम, 2014 का संदर्भ देते हुए निम्नलिखित के उत्तर दें:

- (i) ब्लो (निधि) लिमिटेड की निवल स्वाधिकृत निधियों की गणना कीजिए।
- (ii) ब्लो (निधि) लिमिटेड द्वारा स्वीकार की जा सकने वाली जमा की अधिकतम राशि की गणना करें।

(4 अंक)

- (b) मई 2021 के महीने में एक छोटी सी कंपनी, अनूर शीप प्राइवेट लिमिटेड ने एक राजनीतिक दल को एक लाख का दान दिया। कंपनी तीन वित्तीय वर्षों से कम समय से अस्तित्व में है और इसने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। आखिरकार, कंपनी की कानूनी स्थिति की अनदेखी करते हुए, कंपनी पर निर्णायक अधिकारी (कंपनियों के पंजीयक) द्वारा ₹5 लाख का जुर्माना लगाया गया। अनूर शीप प्राइवेट लिमिटेड ने कम जुर्माना लगाने के अनुरोध के साथ कंपनी पंजीयक से संपर्क किया। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित का उत्तर दें:

- (i) क्या कम जुर्माना लगाना संभव है?
- (ii) यदि ऐसा है, तो कंपनी द्वारा देय जुर्माने की मात्रा की गणना करें।

(4 अंक)

- (c) आगुन्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड [निगमित देनदार] को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (2006 का 27) अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत एक लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस पर अपने लेनदारों का 60 लाख रुपये बकाया है। कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, निगमित देनदार भुगतान अनुसूची के अनुसार विविध देनदारों से पैसा वसूल करने की स्थिति में नहीं था और यह विविध लेनदारों को देय राशि का भुगतान करने में चूक करता है। कॉरपोरट कर्जदार ने दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत पूर्व-आवरित दिवालिया समाधान प्रक्रिया [पीपीआईआरपी] अपनाने का फैसला किया और तदनुसार पीपीआईआरपी शुरू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए।

1. कॉरपोरट देनदार के वित्तीय लेनदारों ने, जो इससे संबंधित पक्ष नहीं हैं, वित्तीय ऋण के मूल्य में 66% का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री प्योर, दिवालिया पेशेवर को

पीपीआईआरपी के संचालन के लिए समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया।

2. निगमित देनदार के निदेशक मंडल के बहुमत ने घोषणा की है कि पीपीआईआरपी किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के लिए शुरू नहीं किया जा रहा है और घोषणा में और कुछ भी शामिल नहीं है।
3. कॉरपोरेट देनदार के सदस्यों ने पीपीआईआरपी शुरू करने के लिए एक आवेदन दाखिल करने को मंजूरी देते हुए एक साधारण संकल्प पारित किया।

किसी भी मामले में वित्तीय लेनदारों/निदेशक मंडल से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, पीपीआईआरपी शुरू करने के लिए एनसीएलटी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के लिए निम्नलिखित मामलों पर सलाह दें।

- (i) क्या श्रीमान.इज़ प्योर एज़ रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल के नाम का प्रस्ताव करने वाले वित्तीय लेनदारों का कृत्य वैध है?
- (ii) क्या समिति द्वारा की गई घोषणा आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार है?
- (iii) क्या कंपनी के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव IBC की आवश्यकताओं के अनुरूप है?
- (iv) क्या किसी अन्य मामले पर वित्तीय लेनदारों/निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता है? यदि हां, तो आईबीसी के संगत प्रावधानों का उल्लेख करें।

(6 अंक)

उत्तर

- (a) (i) ब्लो (निधि) लिमिटेड प्रावधान की निवल स्वाधिकृत निधियों की गणना

निधि नियमावली, 2014 के नियम 3 के अनुसार, "निवल स्वाधिकृत निधि" का अर्थ चुकता हिस्सेदारी शेयर पूंजी और मुक्त भंडार का कुल योग है, जो पिछले लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दिखाई देने वाली संचित हानियों और अमूर्त संपत्तियों से घटाया गया है।

बशर्ते कि अधिमानी शेयरों के निर्गम से प्राप्त होने वाली राशि को शुद्ध स्वामित्व वाली निधियों की गणना के लिए शामिल नहीं किया जा

गणना

विवरण (ब्यौरा)	राशि ₹ में
प्रदत्त हिस्सेदारी शेयर पूंजी	15,00,000
मुक्त संचय	1,00,000
घटाएँ: अमूर्त संपत्ति	(2,00,000)
शुद्ध स्वामित्व वाली निधि	14,00,000

- (ii) निधि नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ब्लो (निधि) लिमिटेड द्वारा स्वीकार की जा सकने वाली अधिकतम राशि की गणना, एक निधि अपने अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार अपने शुद्ध स्वामित्व वाले निधि (एनओएफ) के बीस गुना से अधिक जमा स्वीकार नहीं करेगी।

इसलिए, ब्लो (निधल) लिमिटेड जमा के रूप में अधिकतम ₹2,80,00,000 (₹14,00,000 का 20 गुना) स्वीकार कर सकता है।

- (b) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 446बी के अनुसार, यदि एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी, स्टार्ट अप कंपनी या निर्माता कंपनी, या इसके किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का पालन न करने पर जुर्माना देय है चूककर्ता, या ऐसी कंपनी के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति, तो ऐसी कंपनी, चूककर्ता अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, जुर्माने का भागी होगा जो जुर्माने के आधे से अधिक नहीं होगा कंपनी के मामले में अधिकतम दो लाख रुपये और चूक करने वाले अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में एक लाख रुपये, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रावधानों में निर्दिष्ट है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 में यह प्रावधान है कि

- (1) एक कंपनी जो तीन वित्तीय वर्षों से कम समय से अस्तित्व में है, उसे किसी भी राजनीतिक दल में योगदान करने की अनुमति नहीं है
- (2) यदि कोई कंपनी धारा 182 के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई अंशदान करती है, तो वह कंपनी इस प्रकार किए गए योगदान की राशि के पांच गुना तक के जुर्माने से दंडनीय होगी।

उपरोक्त प्रावधानों और प्रश्न के तथ्यों के आलोक में, निम्नलिखित उत्तर हैं

- (i) क्या कम जुर्माना लगाना संभव है?

हां, कम जुर्माना लगाना संभव है क्योंकि अनूर शीप प्राइवेट लिमिटेड एक छोटी कंपनी है और धारा 446बी छोटी कंपनियों के लिए कम जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है।

(ii) जुर्माना की मात्रा की गणना

अनूर भेड़ प्राइवेट लिमिटेड ने धारा 182 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और दंड के लिए उत्तरदायी है (अधिकतम ₹1,00,000 का 5 गुना), हालांकि, यह एक छोटी कंपनी होने के कारण ₹2,00,000 [(1/2) से अधिक की राशि के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। (5,00,000 की) अधिकतम दो लाख रुपये के अधीन।

(c) पूर्व-आवरित इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (PPIRP) [इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 54A - 54P]।

निगमित देनदार पूर्व-आवरित दिवालिया समाधान प्रक्रिया के लिए पात्र हैं

आईबीसी, 2016 की धारा 54ए(1) के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की धारा 7(1) के तहत सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत निगमित देनदार के संबंध में पीपीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। विकास अधिनियम, 2006।

(i) क्या श्रीमान.प्योर संकल्प पेशेवर के रूप में नाम का प्रस्ताव करने वाले वित्तीय लेनदारों का अधिनियम वैध है?

आईबीसी, 2016 की धारा 54ए(2) के संदर्भ में पीपीआईआरपी शुरू करने के लिए एक निगमित ऋणी के संबंध में एक आवेदन किया जा सकता है, जो धारा 54ए2(ई) में निर्दिष्ट शर्त के अधीन धारा 4 में निर्दिष्ट चूक करता है, जिससे वित्तीय निगमित देनदार के लेनदार, जो इसके संबंधित पक्ष नहीं हैं, इस तरह की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस तरह से निर्दिष्ट किया जा सकता है, ने निगमित देनदार और वित्तीय लेनदारों के पीपीआईआरपी के संचालन के लिए समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किए जाने वाले दिवालिया पेशेवर के नाम का प्रस्ताव दिया है। निगमित ऋणी जो इसके संबंधित पक्ष नहीं हैं, ऐसे लेनदारों के कारण वित्तीय ऋण के मूल्य में 66% से कम का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ऐसे रूप में अनुमोदित किया जा सकता है जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

इसलिए, उपरोक्त के मद्देनजर, श्रीमान.प्योर के नाम को रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में प्रस्तावित करने वाले वित्तीय लेनदारों का कार्य वैध है।

(ii) क्या समिति द्वारा की गई घोषणाएं आईबीसी, 2016 के प्रावधानों के अनुसार हैं?

आईबीसी, 2016 की धारा 54ए(2)(एफ) के संदर्भ में, निगमित देनदार के अधिकांश निदेशकों या भागीदारों, जैसा भी मामला हो, ने एक घोषणा की है, इस तरह के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है कि:

- (i) निगमित देनदार 90 दिनों की एक निश्चित समय अवधि के भीतर पीपीआईआरपी शुरू करने के लिए एक आवेदन दाखिल करेगा,
- (ii) कि पीपीआईआरपी किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के लिए शुरू नहीं किया जा रहा है।
- (iii) खंड (e) के तहत समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित दिवाला पेशेवर का नाम;

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निगमित देनदार के निदेशक मंडल के बहुमत द्वारा यह घोषणा कि पीपीआईआरपी किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के लिए शुरू नहीं किया जा रहा है, पर्याप्त नहीं है। घोषणा में उपरोक्त खंड 2(एफ)(i) और (iii) में निहित मामले भी शामिल होंगे।

(iii) क्या सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव आईबीसी, 2016 की आवश्यकताओं के अनुरूप है?

संख्या अधिनियम की आवश्यकता है कि कॉर्पोरेट देनदार के सदस्य एक विशेष प्रस्ताव पारित करें, या भागीदारों की कुल संख्या का कम से कम तीन-चौथाई, जैसा भी मामला हो, कॉर्पोरेट देनदार ने पूर्व-आवरित दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन दाखिल करने का अनुमोदन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है।

(iv) वित्तीय लेनदारों / निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकताएं

हाँ। निगमित देनदार अपने वित्तीय लेनदारों से अनुमोदन प्राप्त करेगा, जो कम से कम छियासठ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे लेनदारों को देय वित्तीय ऋण के मूल्य में, पूर्व-पैक दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन दाखिल करने के लिए।

निगमित देनदार के निदेशकों के बहुमत से, एक घोषणा की आवश्यकता होती है जिसमें कहा गया है कि कॉर्पोरेट देनदार नब्बे दिनों से अधिक नहीं एक निश्चित समय अवधि के भीतर पूर्व-आवरित दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन दाखिल करेगा; और प्रस्ताव पेशेवर के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित दिवालिया पेशेवर का नाम उनमें शामिल होगा।

प्रश्न 6

- (a) ए, बी और सी एक्स लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक हैं। ए को 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था, बी को 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और सी को 5 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

सभी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल/कार्यकाल 30 सितंबर, 2022 को समाप्त हो जाएगा। लिमिटेड उपरोक्त स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति पर विचार करने की योजना बना रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप सलाह दें कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ए, बी और सी को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में फिर से नियुक्त किया जा सकता है? (4 अंक)

या

श्रीमान.जैक, एक युवा और ऊर्जावान 24 वर्षीय अमेरिकी नागरिक रोजगार लेने के लिए जनवरी, 2021 के महीने में भारत आए। वह नौकरी के लिए आखेटकर रहा है और भारत में रह रहा है। मैसर्स एनएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड एक सूचीबद्ध कंपनी है जो ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित करने में लगी हुई है। को हुई वार्षिक आम बैठक में इस कंपनी ने श्रीमान.जैक को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया 11 नवंबर, 2021, कुछ नियमों और शर्तों पर। उपरोक्त जानकारी के आधार पर, आपसे अनुरोध है कि अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित को मान्य करें:

- (i) प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए श्री जैक की पात्रता।
- (ii) यदि कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है तो क्या आपका उत्तर भिन्न होगा? (एसईजेड)?
- (b) एबीसी लिमिटेड ने आपकी परीक्षा के लिए निम्नलिखित बातें रखी हैं। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 15 जुलाई, 2021 को बुलाई गई थी। जबकि एक निदेशक ने समिति की बैठक में शारीरिक रूप से भाग लिया, कंपनी के अन्य सभी पांच निदेशकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों से बैठक में भाग लिया और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वार्षिक वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए आपसे निम्नलिखित को सत्यापित करने का अनुरोध किया जाता है:
 - (i) उक्त बैठक के लिए कोरम की अनुपालन आवश्यकता।
 - (ii) 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का अनुमोदन।
- (c) एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक स्टार्ट-अप कंपनी है। कंपनी एक शेयरधारक से कार्यशील पूंजी के लिए आंशिक रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के रूप में 3 वर्ष के लिए 3 मिलियन अमरीकी डालर के स्वचालित मार्ग के तहत बाहरी

(4 अंक)

वाणिज्यिक उधार लेने का इरादा रखती है।

आपसे अनुरोध है कि आप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता, रूपों और राशि पर कंपनी को सलाह दें।

(3 अंक)

- (d) राम, वित्तीय लेनदार, एसंग्रहित लिमिटेड (निगमित देनदार) द्वारा जारी किए गए मोचन प्रीमियम के साथ परिपक्वता पर देय 'वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण-पत्र अनुबंध (ओसीडीबी)' का एक निवेशक और ऋण-पत्र धारक था। 2016 में ₹3 करोड़ की राशि के शून्य ब्याज वाले ओसीडीबी बॉन्ड परिपक्व हो गए थे। कॉरपोरेट देनदार देय तिथि में इस ऋण का निर्वहन करने में विफल रहा। राम ने एनसीएलटी के समक्ष निगमित दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया। दिए गए तथ्यों के आलोक में दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों की सलाह दें:

- (i) क्या राम सीआईआरपी की शुरुआत के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए पात्र है?
- (ii) क्या ऋण-पत्र अनुबंध का मोचन, परिपक्वता तिथि पर देय, ऋण की राशि है?

(3 अंक)

उत्तर

- (a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) और (11) के अनुसार:

कार्यकाल: एक स्वतंत्र निदेशक किसी कंपनी के समिति में लगातार 5 वर्षों तक पद धारण करेगा।

पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता: वह कंपनी द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करने और बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसी नियुक्ति के प्रकटीकरण पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

पद धारण करने की सीमा: एक स्वतंत्र निदेशक लगातार 2 से अधिक कार्यकाल के लिए पद धारण नहीं करेगा।

नियुक्ति के लिए कूलिंग अवधि: हालाँकि,, वह एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 3 वर्ष की समाप्ति के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

ए. की नियुक्ति

मौजूदा मामले में, ए को 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था, इसलिए उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने के बाद उसे फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

बी और सी की नियुक्ति

बी को 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, इसलिए उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने के बाद उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

सी को 5 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, उसे लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है। हालाँकि,, वह एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 3 वर्ष की समाप्ति के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

या

अनुसूची V के अनुसार नियुक्ति के लिए अतिरिक्त पात्रता शर्तें:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के भाग I में केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के लिए अतिरिक्त पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। शर्त (4) के अधीन, नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए।

स्पष्टीकरण । स्पष्ट करता है कि भारत में निवासी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लगातार बारह महीने की अवधि के लिए भारत में रह रहा है, प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से ठीक पहले और जो भारत में निम्नलिखित कारणों से रहने के लिए आया है, -

- (a) भारत में रोजगार लेने या करने के लिए या
- (b) भारत में व्यापार करने या छुट्टी मनाने के लिए।

स्पष्टीकरण II स्पष्ट करता है कि उपरोक्त शर्त विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में कंपनियों पर लागू नहीं होगी।

(i) एमडी के रूप में नियुक्त होने के लिए श्री जैक की पात्रता

इस मामले में श्री जैक, एक अमेरिकी नागरिक जनवरी, 2021 के महीने में रोजगार लेने के लिए भारत आया था। उन्हें 11 नवंबर, 2021 को एनएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

चूंकि श्री जैक 11 नवंबर, 2021 से ठीक पहले बारह महीनों की लगातार अवधि के लिए भारत में नहीं रहे, इसलिए वे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने के पात्र नहीं हैं।

(ii) यदि कंपनी एसईजेड में स्थित है

यदि कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित है, तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी और श्री जैक प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं।

- (b) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 174(1) के अनुसार, समिति की बैठक के लिए कोरम इसकी कुल संख्या का एक तिहाई या दो निदेशकों, जो भी अधिक हो, का होगा।

अधिनियम की धारा 173 (2) एक कंपनी के निदेशकों को निम्नलिखित तरीके से बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की अनुमति देती है:

- ♦ व्यक्तिगत रूप से
- ♦ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
- ♦ नियम, 2014 के अन्य कंपनियां श्रव्य-द्रश्य (बैठकों का मतलब निर्धारित समिति और उसके नियम 3 शक्तियों के तहत)

(i) कोरम अनुपालन

वर्तमान मामले में, चूंकि एबीसी लिमिटेड में कुल 6 निदेशक हैं, कोरम 2 (6 का 1/3 या 2, जो भी अधिक हो) होगा। चूंकि, एक निदेशक ने बैठक में शारीरिक रूप से भाग लिया और अन्य सभी पांच निदेशकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/श्रव्य-द्रश्य माध्यमों से भाग लिया, इसका तात्पर्य है कि सभी निदेशक बैठक में शामिल हुए और कोरम अनुपालन है।

(ii) वित्तीय विवरणों का अनुमोदन:

चूंकि समिति की बैठक का कोरम सभी छह निदेशकों की उपस्थिति के साथ अनुपालन किया जाता है, इसलिए 15 जुलाई, 2021 को आयोजित समिति की बैठक में वित्तीय विवरण का अनुमोदन मान्य है।

इसके अलावा, कंपनी (समिति की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुमोदन सहित कुछ मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य श्रव्य-द्रश्य माध्यमों से बैठक में नहीं निपटाया जा सकता है। हालांकि, अधिसूचना जीएसआर शक्तियाँ) नियम, 2014, कंपनी (समिति की बैठक और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के प्रवर्तन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य-द्रश्य माध्यमों के माध्यम से बैठक में निपटाए जाने वाले मामलों से निपटने वाले नियम 4 को छोड़ दिया गया था। . इसलिए, कंपनी ने 15 जुलाई, 2021 को आयोजित समिति की बैठक में वार्षिक वित्तीय विवरणों को मंजूरी देते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

- (c) एक्सवाइजेड लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मुख्य निदेश संख्या 5/2018 -19 में निहित दिशानिर्देशों के आधार पर निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

स्टार्ट-अप के लिए ईसीबी सुविधा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निम्नलिखित ढांचे के अनुसार स्टार्टअप्स को स्वचालित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति देने की अनुमति है:

पात्रता: ECB जुटाने की तारीख को केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त एक इकाई। परिपक्वता: न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 3 वर्ष होगी।

फॉर्म: उधार ऋण या गैर-परिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय या आंशिक रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के रूप में हो सकता है।

ईसीबी की राशि: प्रति स्टार्टअप उधार 3 मिलियन अमरीकी डालर या प्रति वित्तीय वर्ष के बराबर या तो INR या किसी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा या दोनों के संयोजन तक सीमित होगा।

- (d) वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण-पत्र अनुबंध (ओसीडीबी) ऋण प्रतिभूतियां हैं जो जारीकर्ता को पूंजी जुटाने की अनुमति देती हैं और बदले में जारीकर्ता परिपक्वता तक निवेशक को ब्याज देता है।

- (i) क्या राम सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन करने का पात्र है?

दिए गए मामले में, राम, एसंग्रहित लिमिटेड (कॉरपोडर देनदार) द्वारा जारी परिपक्वता पर देय ओसीडीबी का ऋण-पत्रधारक था, जिसे वह देय तिथि पर निर्वहन करने में विफल रहा।

धारा 21(6ए) के अनुसार, जहां एक वित्तीय ऋण प्रतिभूतियों या जमा के रूप में हैं और वित्तीय ऋण की शर्तें सभी वित्तीय लेनदारों, ऐसे संरक्षक या दलाल के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एक संरक्षक या दलाल की नियुक्ति के लिए प्रदान करती हैं। ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से कार्य करेगा;

संहिता की धारा 7 के परंतुक के अनुसार, कॉरपोडर ऋणी के खिलाफ निगमित दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि यानी संरक्षक या दलाल के माध्यम से एक ही वर्ग में निर्दिष्ट लेनदारों की आवश्यक संख्या द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया जाएगा।

तदनुसार, श्री राम सीआईआरपी की शुरुआत के लिए एक आवेदन दाखिल करने के हकदार हैं।

(ii) क्या ऋण-पत्र अनुबंध का मोचन, परिपक्वता तिथि पर देय, ऋण की राशि है?

हां, परिपक्वता पर देय ऋण-पत्र अनुबंध का मोचन ऋण के बराबर होता है। संहिता के तहत ऋण का अर्थ किसी दावे के संबंध में एक ऋण या ऋण है जो किसी भी व्यक्ति से देय है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं। [धारा 3 (11)]

वित्तीय ऋण - "वित्तीय ऋण" का अर्थ ब्याज सहित एक ऋण है, यदि कोई हो, जो धन के समय मूल्य के प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है और इसमें किसी भी नोट खरीद सुविधा या बॉन्ड, नोट, ऋण-पत्र के मुद्दे के अनुसार जुटाई गई राशि शामिल है। ऋण स्टॉक या कोई समान साधन।